भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4208

उत्तर दिनांक 26/03/2025 को दिया गया

परमाणु विद्युत उत्पादन में वृद्धि

4208. श्री अ. मनि

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार ने अगले पांच वर्षों में देश की परमाणु विद्युत उत्पादन क्षमता में 70 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) तमिलनाडु राज्य में कितने परमाणु विद्युत केन्द्र कार्य कर रहे हैं और उनकी कुल क्षमता कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने तमिलनाडु में एक ऐसे परमाणु विद्युत परियोजना का प्रस्ताव किया है जो विश्व में सबसे बड़ी परमाणु विद्युत उत्पादन परियोजना होगी और यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में परमाणु विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) व (ख) वर्ष 2024 में तत्समय मौजूदा क्षमता 8180 मेगावाट (लगभग 70% की वृद्धि) को पांच वर्षों में 14080 मेगावाट क्षमता तक वृद्धि किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आरएपीपी 7 व 8 (2X700 मेगावाट), केकेएनपीपी 3 व 4 (2X1000 मेगावाट), केकेएनपीपी 5 व 6 (2X1000 मेगावाट) और भाविनि द्वारा निर्मित पीएफबीआर (500 मेगावाट) को चरणबद्ध पूर्णता के माध्यम से क्षमता वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है। परियोजनाओं की प्रगति की बारीकी से निगरानी की जा रही है और आरएपीएस-7 को 17 मार्च, 2025 को ग्रिड से जोड़ा जा चुका है।

(ग) तमिलनाडु राज्य में कुल 2440 मेगावाट क्षमता वाले चार नाभिकीय विद्युत संयंत्र प्रचालनरत हैं।

(घ) तमिलनाडु में कुडनकुलम स्थल पर, दो यूनिटें केकेएनपीपी 1 व 2 (2X1000 मेगावाट) पहले से ही प्रचालित हैं और चार यूनिटें केकेएनपीपी 3 व 4 (2X1000 मेगावाट) तथा केकेएनपीपी 5 व 6 (2X1000 मेगावाट) निर्माणाधीन हैं। इनके पूरा होने पर, 6000 मेगावाट की कुल क्षमता सहित कुडनकुलम स्थल के देश का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र बनने की आशा है। केकेएनपीपी 3 से 6 के वर्ष 2027-28 तक क्रमिक रूप से पूरा होने की आशा है।

(ङ) सरकार ने और नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के लिए मंजूरी प्रदान की है और पर्याप्त मात्रा में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित की है।

*****